मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 66400/97

फार्म हाउसों को बचाने उतरी हरियाणा सरकार 3
डेयरी ऋण पर 25 फीसदी अनुदान योजना फिर शुरु 4
बेशर्म भाजपाई टूटी सड़कों पर निकाल रहे तिरंगा यात्रा 5
खोरी एक, हरामखोरी अनेक! 6
सरकारी पैसे में शहर की संस्थाओं ने की हेराफेरी 8

वर्ष 34 | अंक 39 | फरीदाबाद | 8-14 अगस्त 2021 | फोन-8851091460 | 3.00 ₹

एनआईटी में अवैध निर्माण एक ही सिंडीकेट के 5 लोगों की देन

कमिश्नर यशपाल यादव द्वारा कराये गये सर्वे की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी है

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: एनआईटी में गली-गली खोरी बसाने वाला माफिया प्रशासन, पुलिस और एमसीएफ की पकड़ से बाहर हैं। इस माफिया के कई चेहरे हैं। एनआईटी नंबर 1, 2, 3, 5 में अवैध फ्लोर, सरकारी जमीनों पर निर्माणों, बिना स्टिल्ट पार्किंग निर्माण, नाले पर निर्माण, रेजिडेंशल में कमर्शल का निर्माण यानी अवैध प्रॉपर्टी के धंधे में जितने भी प्रकार के नियम विरुद्ध काम हो सकते हैं, वो यही सिंडीकेट कर रहा है। यही ग्रुप ओयो खोल रहा है और उनमें आये दिन इस सिंडीकेट की दावतें होती हैं, जिनमें छोटे प्रॉपर्टी डीलरों को बुलाकर उनके कमरों में लड़कियां भेजी जाती हैं। वहां कई-कई करोड़ की अवैध लॉटरी खेली जाती है। कुछ में सट्टा खेला जाता है।

मौजूदा नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव को जब बीच में कुछ दिन के लिए एमसीएफ का चार्ज मिला था तो उन्होंने एनआईटी में अवैध निर्माणों का एक सर्वे कराया था, उस सर्वे के दौरान सिंडीकेट का नाम उभरा था। लेकिन सर्वे रिपोर्ट आने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। समझा जाता है कि ये कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि कई आला अफसरों ने भी इसी माफिया के जरिए एनआईटी की तमाम प्रॉपर्टी में निवेश कर रखा है। संयोग से यशपाल यादव को अब एमसीएफ का पूरा चार्ज मिल गया है, ऐसे में सवाल है कि क्या एमसीएफ के मौजूदा कमिश्नर इस सिंडीकेट पर कार्रवाई की हिम्मत जुटा पाएंगे।

कौन हैं ये 5 चेहरे

एनआईटी के अवैध रीयल एस्टेट कारोबार में पैसा लगाने वाले बैजू, विरमानी, नितिन, संजय अदलखा, अमित आहूजा छोटे-मोटे नाम नहीं हैं। इनमें से कई भाजपा नेता बन गए हैं। कुछ को मंत्रियों और भाजपा विधायकों का संरक्षण मिला हुआ है। इन सभी के नाम हरियाणा सरकार की विजिलेंस जांच में, एफआईआर में आये हैं। इसलिए हमें भी इनकी पहचान आपको बतानी पड़ी।

बैजू की कहानी दिलचस्प है। बैजू खानदानी रईस या पुरानी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। उसने छोटी-छोटी प्रॉपर्टी से अपने करियर की शुरुआत की और एमसीएफ के अफसरों की मदद से एक अरब रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी खड़ी कर ली। एनआईटी नं.1 में तिकोना पार्क सब्जी मंडी के सामने मार्केट में इसने सारे नियम तोड़कर एक बड़ी बिल्डिंग बनाई और फिर उसमें सब डिवीजन कर दिए। हाल ही में हरियाणा सरकार प्लॉट सब डिवीजन को वैध बनाने की जो विवादास्पद पॉलिसी लाई थी, वो इसी गैंग और इनके संरक्षणदाता नेताओं के कहने पर लाई गई थी। भाखरी गांव में इसकी एक फैक्ट्री भी है लेकिन बैजू का मुख्य धंधा प्रॉपर्टी बिजनेस है। इसके गैंग में नितिन भी है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के कई अफसरों ने अपनी अवैध कमाई इनके जरिए रीयल एस्टेट बिजनेस में निवेश कर रखी है। इसके अलावा बैजू ब्याज पर पैसे देने का अवैध धंधा करता है।

नितिन आयो और अन्य होटलों में कई-कई करोड़ की अवैध लॉटरी की पार्टी आयोजित करता है। इस पार्टी में छोटे प्रॉपर्टी डीलर शामिल होते हैं। उस पार्टी में दिल्ली से लड़कियां बुलाई जाती हैं। इस पार्टी में जिसकी भी पांच-दस करोड़ की लाटरी खुलती है, वो वहीं पर बैजू या नितिन के जरिए उनकी प्रॉपर्टी में निवेश करने की घोषणा करता है। एमसीएफ की एसआईटी जांच में भी बैजू और नितिन का नाम आ चुका है। हरियाणा सरकार की सीआईडी, विजिलेंस के पास भी बैजू और नितिन की ढेरों शिकायतें लिखित रूप में पहुंची हुई हैं। मजदूर मोर्चा ने पिछले दिनों बडखल रोड पर (सेक्टर 21 डी से एसजीएम नगर जाने वाली सड़क के कोने पर) सरकारी जमीन पर दुकानें बनाने की जो खबर छापी थी, उसमें भी नितिन का नाम आया था। उस मामले में 2020 में एमसीएफ दीवार गिराने की कार्रवाई कर चुका है। लेकिन वहां लॉकडाउन के दौरान फिर से दुकानें खड़ी कर दी गईं। इस बार करनाल के भाजपा सांसद का नाम लेकर 1000 गज सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया।

एनएच 3 में बनाई गई तमाम अवैध बिल्डिंग की एक-एक ईंट से विरमानी का नाम आ रहा है। विरमानी बंधु भी बैजू और नितिन गैंग का हिस्सा है। एनएच 3 सी 164 बिल्डिंग पर तो एमसीएफ कार्रवाई भी कर चुका है लेकिन कुछ दिनों के बाद पूरी बिल्डिंग फिर से बना दी गई। इस बिल्डिंग पर एमसीएफ में ली गई रिश्वत का असर इतना था कि मौके पर जब सुमेर सिंह नामक कर्मचारी तोड़ने गया तो वहां महेन्द्र नामक एमसीएफ कर्मचारी ने विरोध किया। दोनों में हाथापाई भी हुई। विरमानी विवादास्पद बिल्डिंगों और झगड़े वाली बिल्डिंगों को भी खरीद लेता है। छानबीन से पता चला है कि अकेले एनआईटी इलाके में विरमानी बंधुओं की ऐसी बीस बिल्डिंगें हैं जो अवैध निर्माण की कहानी कह रहे हैं। किसी को बिना सीएलयू बनाया गया। किसी में स्टिल्ट पार्किंग नहीं है। किसी का नक्शा पास नहीं है। विरमानी की तमाम बिल्डिंगों में बिना एफएआर परचेज किए, छज्जे तक पर कमरे खड़े कर दिए गए हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

एनएच 3 में संजय अदलखा भी एक बड़ा बिल्डर है और कई अवैध भवनों को बनाने से उसका नाम जुड़ा है। 3जे-1 फ्रंटियर कॉलोनी में बिल्डिंग बनाने को लेकर तो एमसीएफ ने संजय अदलखा के नाम से एफआईआर भी कराई।

इस बिल्डिंग के बनने की कहानी भी दिलचस्प है। जब इसे बनाया जा रहा था तो संजय अदलखा ने बिल्डिंग पर विधायक सीमा त्रिखा का बड़ा सा फोटो लगाकर यहां भाजपा कार्यालय का बैनर लगा दिया।

एमसीएफ अफसरों को उसकी चालाकी तो समझ में आ गई लेकिन उन्होंने खुद को बचाने के लिए संजय अदलखा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। इसके बावजूद बिल्डिंग बन गई और उसके बाद उस बैनर को हटा दिया गया। सीमा त्रिखा और भाजपा ने संजय अदलखा से कभी ऐतराज नहीं **शेष पेज 2 पर**

एनएच-3 में जब अवैध बिल्डिंग बन रही थी तो उस समय यह पोस्टर लगाया गया था, बनने के बाद इसे उतार लिया गया

12 अगस्त को हो सकती है बड़ी कार्रवाई

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फ़रीदाबाद: हरियाणा सरकार ने एनआईटी इलाक़े में तोड़फोड़ की बड़ी कार्रवाई का आदेश जारी किया है। इस आदेश के मद्देनज़र एमसीएफ एनएच 1, 3 और 5 में 12 अगस्त को बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ कर सकता है। दरअसल, एक एसआईटी रिपोर्ट पर हरियाणा सरकार ने एमसीएफ कमिश्नर से कार्रवाई रिपोर्ट माँगी है।

एनआईटी नंबर 1, 2, 3, और 5 में अवैध निर्माण की रिपोर्ट मिलने पर सरकार ने एक एसआईटी गठित कर इसकी जाँच का आदेश दिया था। एसआईटी का नेतृत्व एमसीएफ के ज्वाइंट कमिश्नर स्तर के अधिकारी ने किया था। एसआईटी की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने कमिश्नर से आगे की रिपोर्ट माँगी है।

सूत्रों ने बताया कि शासन से मिले निर्देशों के तहत एसडीओ एनफोर्समेंट ने 12 अगस्त के लिए पुलिस प्रशासन से पुलिस बल माँगा है। पुलिस अधिकारियों से एसडीओ एनफोर्समेंट ने कहा है कि क़रीब 500 पुलिसकर्मियों और 150 महिला पुलिसकर्मियों की सेवाएँ 12 अगस्त को सुबह दस बजे से चाहिए।

एमसीएफ में तैनात किए गए कमिश्नर यशपाल यादव की देखरेख में पहली बार बड़ी कार्रवाई की संभावनाएँ बन रही है। इससे पहले जब उनके पास यहाँ का अतिरिक्त कार्यभार था तो वह कुछ ख़ास नहीं कर सके थे लेकिन शासन के निर्देश पर अब उन्हें मैदान में उतरना पड़ेगा।

कोरोना में लोग मरते रहे सीएमओ के स्टॉक में रेमडेसिविर सड़ते रहे

फ़रीदाबाद (म.मो.) कोरोना कहर के नाम पर अन्य सरकारों की तरह हरियाणा सरकार ने भी करोड़ों रुपये के रेमडेसिविर इन्जेक्शन खरीदे। सरकार द्वारा इन्हें तमाम ज़िला अस्पतालों में भेज दिया। कोरोना के डर से लोग अपने परिजनों को बचाने के लिये इस इन्जेक्शन को काला बाजारियों से 20-30 हजार रुपये तक में खरीद कर लगवाते रहे। सरकार द्वारा अपने गोदामों में भरे जाने के साथ-साथ काला बाजारियों ने भी इसे अपने गोदामों में भर रखा था। हरियाणा सरकार ने इसकी काला बाजारी रोकने के नाम पर जो नौटंकी की वह और भी भयानक थी।

सरकार द्वारा तय किया गया कि सरकारी अस्पतालों में यह इन्जेक्शन जरूरत-मंदों को, मुफ्त लगाया जायेगा और व्यापारिक अस्पतालों को बेचा जायेगा। लेकिन व्यापारिक अस्पतालों द्वारा भी इसे खरीद पाना कोई सरल काम नहीं था। इस अस्पताल को कितने इन्जेक्शन देने हैं या नहीं देने हैं इसके लिये ज़िला स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी की अध्यक्ष बल्लभगढ की एसडीएम को बनाया गया। सदस्य के तौर पर सेवा निवृत सिविल सर्जन वीर सिंह सहरावत, डिप्टी सीएमओ अनूप व एक दो अन्य को बनाया गया। इनकी बैठक प्रति दिन एसडीएम बल्लभगढ के कार्यालय में होती थी। कुछ दिन बाद इस कमेटी में फेर-बदल करके एसडीएम की जगह एडीसी, आईएमए की ज़िला प्रधान डॉक्टर हसीजा व सीएमओ कार्यालय के चीफ़ फ़ार्मासिस्ट कुलदीप कटारिया को बनाया गया।

दोनों ही कमेटियों के काम-काज में कोई विशेष अंतर नहीं रहा। इन कमेटियों के पास शहर के तमाम बड़े व्यापारिक अस्पतालों से इस इंजेक्शन की मांग भारी मात्रा में आती थी। लेकिन बहुत कम अस्पतालों को इन्जेक्शन दिये गये इसके पीछे एम्स नई दिल्ली द्वारा जारी की गई गाइड लाइन्स को बताया जा रहा है। कुछ इन्जेक्शन बीके अस्पताल में भर्ती मरीज़ों के लिये भी जारी किये गये थे। लेकिन जब सम्बन्धित डॉक्टर को पता चला कि ये इन्जेक्शन उनके मरीजों को लगने की बजाय स्टाफ़ के कुछ बेईमान कर्मचारी ब्लैक में बेचकर खा रहे हैं तो उन्होंने बजाय चोरों को पकड़वाने के इन्जेक्शन लिखने ही बंद कर दिये।

इन सब हालातों की वजह से आज यहां 7100 इंजेक्शन का स्टॉक एक्सपायर होने की कगार पर खड़ा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार चार विभिन्न कम्पनियों से खरीदे गये इन इन्जेक्शनों के दाम 2800, 1900 व 1500 रुपये हैं। औसतभाव यदि 2000 रुपये प्रति इन्जेक्शन माना जाय तो ये 7100 इन्जेक्शन कितने करोड़ के हुये, पाठक स्वयं हिसाब लगा लें। यह बर्बादी केवल फ़रीदाबाद में ही नहीं बल्कि हर ज़िले में हुई है। यद्यपि हरियाणा सरकार इन इन्जेक्शनों को खपाने के लिये कोरोना की नई लहर का इंतजार कर रही है; परन्तु विशेषज्ञों का मानना है कि ये इन्जेक्शन किसी काम के नहीं हैं। उनके अनुसार कोरोना के इलाज में ये इन्जेक्शन कभी भी लाभकारी नहीं रहे थे। केवल जनता को लूटने-खसोटने के लिये दवा निर्माता कम्पनियों द्वारा यह जाल था। न केवल हरियाणा में बल्कि अन्य राज्यों में भी इसी तरह की लूट मचाई गई थी। मध्यप्रदेश में 36 करोड़ के ऐसे ही इन्जेक्शन एक्सपायर हुये पड़े हैं।

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज : लोग मरते रहे और खजाना लुटता रहा